NIOS PYQ's SOLUTIONS

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS & ANSWERS

APRIL-2025

Your Path to Success

खंड - अ

प्रश्न 1 - निम्नलिखित में से किनके पास दत्तक ग्रहण के लिए पुत्र या 'पलक' को नामित करने की सुविख्यात परम्परा विद्यमान है?

(A) जैन **(B) मुस्लिम**

(C) पारसी **(D) बौद्ध**

उत्तर - (A) जैन

प्रश्न 2 – वैध हिन्दू विवाह के लिए दूल्हे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

(A) 18 वर्ष **(B) 21 वर्ष**

(C) 24 वर्ष **(D) 25 वर्ष**

उत्तर - (B) 21 वर्ष

प्रश्न 3 - भारत में यहूदी समुदाय किस धर्म का पालन करते हैं?

(A) यहूदी धर्म **(B) ईसाई**

(C) इस्लाम **(D) जैन**

उत्तर - (A) यहूदी धर्म

प्रश्न 4 - निम्नलिखित में से कौन-सा हिन्दू कानूनों का स्रोत नहीं है?

(A) वेद **(B) न्यायिक निर्णय**

(C) विधायी कानून **(D) महाभारत**

उत्तर - (D) महाभारत

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 5 - बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है

(A) सूचनाएँ पाना **(B) दण्ड देना**

(C) हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उपस्थिति पाना **(D) निचली अदालत को आदेश जारी करना**

उत्तर - (C) हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उपस्थिति पाना

प्रश्न 6 - निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय उपचारात्मक नहीं है?

(A) क्षतिपूर्ति **(B) विशेष राहत**

(C) दण्ड **(D) गलती करने से रोकना**

उत्तर - (C) दण्ड

प्रश्न 7 - निम्नलिखित में से कौन-सा दण्ड का सिद्धान्त नहीं है?

(A) सुधारात्मक सिद्धान्त **(B) क्षतिपूर्ति सिद्धान्त**

(C) प्रतिकारी सिद्धान्त **(D) आरोपी को क्षमा प्रदान करना**

उत्तर - (D) आरोपी को क्षमा प्रदान करना

प्रश्न 8 - सूचना का अधिकार

(A) मौलिक अधिकार है

(B) सांविधानिक अधिकार है

(C) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्मित एक प्रावधान है

(D) मानवाधिकार है

उत्तर - (A) मौलिक अधिकार है

प्रश्न 9 - अधिष्ठायी कानून निम्नलिखित में से किस एक पर कार्य करता है?

(A) सरकार की कार्यशैली **(B) लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों**

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(C) देश की राजनीति **(D) संसद की कार्य-प्रणाली**

उत्तर - (B) लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों

प्रश्न 10 - आपराधिक कानून निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गतिविधियों को नहीं दर्शाता ?

(A) राज्य **(B) जनता**

(C) समुदाय **(D) प्रदूषण**

उत्तर - (D) प्रदूषण

प्रश्न 11 - निजी कानून में शामिल है

(A) अनुबंध का कानून **(B) क्षति के नियम**

(C) शासन की शक्तियों के प्रयोग पर सीमाएँ **(D) सम्पत्ति का कानून**

उत्तर - (A)अनुबंध का कानून

प्रश्न 12 - संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कौन लागू करता है?

(A) विधायिका **(B) सर्वोच्च न्यायालय**

(C) कार्यपालिका **(D) उच्च न्यायालय**

उत्तर - (C) कार्यपालिका

प्रश्न 13 - उस प्रक्रिया का नाम चुनिए जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से एक समाधान पर पहुँचा जा सके।

(A) विवाचन **(B) मध्यस्थता**

(C) समझौता **(D) वार्ता**

उत्तर - (B) मध्यस्थता

प्रश्न 14 - कौन-से अधिनियम के अन्तर्गत लोक अदालतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हई है?

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(A) विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(B) विधिक प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(C) विधिक सेवाएँ अधिनियम, 1987

(D) अनिवार्य सेवाएँ अधिनियम, 1987

उत्तर - (A) विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987

प्रश्न 15 - निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था?

(A) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर **(B) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद**

(C) जवाहरलाल नेहरू **(D) महात्मा गाँधी**

उत्तर - (A) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर

प्रश्न 16 - निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दर्ज नहीं है?

(A) न्याय **(B) समानता**

(C) स्वतंत्रता **(D) विविधता**

उत्तर - (D) विविधता

प्रश्न 17 - स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत कितनी स्वतंत्रताएँ प्रत्याभूत है?

(A) पाँच **(B) छः**

(C) सात **(D) आठ**

उत्तर - (B) छः

प्रश्न 18 - कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है?

(A) अनुच्छेद 30 **(B) अनुच्छेद 31**

(C) अनुच्छेद 32 **(D) अनुच्छेद 33**

उत्तर - (C) अनुच्छेद 32

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 19 - राष्ट्रपति, राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करते हैं?

(A) 6 **(B) 8**

(C) 10 **(D) 12**

उत्तर - (D) 12

प्रश्न 20 - निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है?

(A) प्रधानमंत्री **(B) भारत का राष्ट्रपति**

(C) संसद **(D) लोकसभा अध्यक्ष**

उत्तर - (B) भारत का राष्ट्रपति

प्रश्न 21 - निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए:

कॉलम-A	कॉलम-B
(a) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869	(i) पारसी परम्परा
(b) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	(ii) यहूदी परम्परा
(c) अवेस्ता	(iii) यहूदी निजी कानून
(d) कासेफ किदुशिम	(iv) ईसाई कानून

उत्तर –

(a) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 — (iv) ईसाई कानून

(b) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 — (iii) यहूदी निजी कानून

(c) अवेस्ता — (i) पारसी परम्परा

(d) कासेफ किदुशिम — (ii) यहूदी परम्परा

प्रश्न 22 - रिक्त स्थानों को भरिए :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

मुस्लिम कानून ________ के _______ को नहीं मानता।

उत्तर – प्रतिनिधित्व, सिद्धान्त

प्रश्न 23 - रिक्त स्थानों को भरिए :

जनहित _________ भारतीय संविधान के अनुच्छेद _________ में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है।

उत्तर – याचिका, अनुच्छेद 39A।

प्रश्न 24 - सही या गलत लिखिए :

(क) आपराधिक कानून में नशा बचावों में से एक बचाव है।

(ख) आपराधिक कानून में दिमागी खराबी को बचाव के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उत्तर –

(क) सही

(ख) गलत

प्रश्न 25 - सही या गलत लिखिए :

(क) आपराधिक कानून राज्य के कानूनों के उल्लंघन पर कार्य करते हैं।

(ख) अधिष्ठायी कानून अपराध एवं उसके उपचारों को परिभाषित करता है।

उत्तर -

(क) सही

(ख) सही

प्रश्न 26 - सही या गलत लिखिए :

(क) लोक कानून उन मुद्दों पर कार्य करते हैं जो व्यक्तियों, नागरिकों अथवा राज्य से संबंधित नहीं होते।

(ख) लोक कानून सरकारी अधिकारियों के कार्यों एवं शक्तियों से सम्बद्ध होते हैं।

उत्तर -

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(क) गलत

(ख) सही

प्रश्न 27 - रिक्त स्थानों को भरिए :

प्रक्रियात्मक कानून अधिकारों के ________ करने की विधि और इनके उल्लंघन की स्थिति में ________ प्राप्त करने के तरीके निर्धारित करते हैं।

उत्तर – प्रवर्तन, उपाय।

प्रश्न 28 - सही या गलत लिखिए :

(क) लोक अदालतें कम कीमत पर तीव्र न्याय प्रदान करती हैं।

(ख) लोक अदालतों का संचालन ग्राम पंचायतें करती हैं।

उत्तर -

(क) सही

(ख) गलत

प्रश्न 29 - रिक्त स्थानों को भरिए :

वार्ता (बातचीत) __________ हल करने हेतु _________ का एक अन्य रूप है।

उत्तर - विवाद, वैकल्पिक विवाद समाधान।

प्रश्न 30 - निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(क) कौन-से संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था?

(ख) प्रारम्भ में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार दर्ज थे?

उत्तर –

(क) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971

(ख) सात (संपत्ति का अधिकार हटने से पहले)

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 31 - सही या गलत लिखिए :

(क) मौलिक अधिकार न्यायसंगत नहीं हैं।

(ख) सम्पत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।

उत्तर –

(क) गलत

(ख) सही

प्रश्न 32 - रिक्त स्थानों को भरिए :

उच्च न्यायालय का _________ नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास किसी न्यायिक पद पर काम करने का _________ वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उत्तर – न्यायाधीश, दस।

प्रश्न 33 - रिक्त स्थानों को भरिए :

किसी राज्य की ________ के ________ सदन को विधान परिषद् कहते हैं।

उत्तर – विधानमंडल, उच्च।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 34 - रिक्त स्थानों को भरिए :

वर्ष _________ में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन _______ में किया गया था।

उत्तर – 1992, रियो डी जनेरियो।

प्रश्न 35 - रिक्त स्थानों को भरिए :

__________ हाउस गैसों के उत्सर्जन का कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक _________ स्तर पर किया गया उपाय है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

उत्तर - ग्रीन, अंतर्राष्ट्रीय ।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 34 - सही या गलत लिखिए :

(क) उपभोक्ता विवाद निवारण एजेन्सियों को तीन भिन्न स्तरों पर स्थापित किया गया है।

(ख) भारत में उपभोक्ता आंदोलन का लक्ष्य व्यापारियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है।

उत्तर –

(क) सही

(ख) गलत

प्रश्न 35 - रिक्त स्थानों को भरिए :

वर्ष 2002 में ________ अधिनियम को ________ में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए लागू किया गया था।

उत्तर – प्रतिस्पर्धा, बाजार ।

खंड - ब

प्रश्न 36 - 'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक कानून' के बीच कोई दो अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - 'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक कानून' के बीच दो मुख्य अंतर :

अंतर का आधार	अधिष्ठायी कानून (Substantive Law)	प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law)
1. कार्य	यह अधिकारों, कर्तव्यों और अपराधों को परिभाषित करता है	यह उन कानूनों को लागू करने का तरीका (प्रक्रिया) बताता है।
2. उद्देश्य	यह बताता है कि "कानून क्या है"।	यह बताता है कि "न्याय कैसे मिलेगा"।

प्रश्न 37 - किसी संवैधानिक सरकार के किन्हीं दो लक्षणों की परख कीजिए।

उत्तर - संवैधानिक सरकार के दो लक्षण :

1. **उदार लोकतांत्रिक राज्य :** सरकार का अधिकार कानूनों से सीमित होता है और जनता के चुने प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है।
2. **कल्याणकारी राज्य :** सरकार का उद्देश्य जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करना है।

OR / अथवा

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं दो अवयवों को उजागर कीजिए।

उत्तर - भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दो अवयव :

1. **राज्य का स्वरूप :** भारत एक 'संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' है, जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और देश अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है।
2. **संविधान के उद्देश्य :** नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है।

प्रश्न 38 - समानता के अधिकार के अन्तर्गत प्रदान की गई किन्हीं चार समानताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के तहत चार प्रमुख समानताएं :

1. **कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) :** सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कानून से समान सुरक्षा पाएंगे।
2. **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15) :** धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
3. **अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) :** सरकारी नौकरी और नियुक्तियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे।
4. **अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17) :** छुआछूत या किसी भी रूप की अस्पृश्यता निषिद्ध और दंडनीय है।

OR / अथवा

स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत दी गई किन्हीं चार स्वतंत्रताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को दी गई चार प्रमुख स्वतंत्रताएं :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :** हर नागरिक अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है।
2. **शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता :** नागरिक बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने के अधिकार के अधिकारी हैं।
3. **संघ बनाने की स्वतंत्रता :** नागरिक अपनी इच्छा अनुसार संघ या संगठन बनाने का अधिकार रखते हैं।
4. **भ्रमण की स्वतंत्रता** : नागरिक भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।

प्रश्न 39 - लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई दो अन्तर उजागर कीजिए।

उत्तर - लोकसभा और राज्यसभा के बीच दो मुख्य अंतर :-

1. **चुनाव प्रक्रिया :** लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

2. **कार्यकाल और स्थायित्व :** लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होते हैं।

प्रश्न 40 - संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्त्व की परख कीजिए।

उत्तर – संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का '**हृदय और आत्मा**' कहा, क्योंकि यह न्यायिक संरक्षण के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 41 - 'प्रदूषण' शब्द की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – प्रदूषण वह अवांछित परिवर्तन है जो वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों को प्रभावित करता है और मनुष्य तथा पूरे पर्यावरण के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुँचाता है। यह हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा के वातावरण में प्रवेश से होता है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 41 - अनुचित कारोबारी व्यवहार में क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले किन्हीं दो अधिनियमों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – अनुचित कारोबारी व्यवहार में क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले दो अधिनियम :

1. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 :** उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है और विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों व प्राधिकरणों की स्थापना करता है।
2. **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 :** उपभोक्ता कल्याण की रक्षा करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है और बाजार में किसी संस्था द्वारा अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकता है।

प्रश्न 42 - 'निजी कानून' का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – 'निजी कानून' कानून की वह शाखा है जो किसी व्यक्ति और उसके परिवार से संबंधित मामलों से निपटती है । इसका महत्त्व निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है :-

1. **पारिवारिक मामलों का नियमन :** यह उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक ग्रहण, संरक्षकता और उत्तराधिकार को नियंत्रित करते हैं ।
2. **अधिकारों और वैधता का निर्धारण :** निजी कानून विवाह की वैधता, पति और पत्नी के संपत्ति के अधिकारों, तलाक, बच्चों की वैधता और वसीयत व उत्तराधिकार के नियमों को तय करता है।
3. **धार्मिक आधार पर अनुप्रयोग** : भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ विभिन्न धर्म हैं, निजी कानून का महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि यह अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी के आधार पर लोगों पर लागू होता है और उनकी विशिष्ट परंपराओं का सम्मान करता है ।
4. **सामाजिक व्यवस्था** : यह विवाह के माध्यम से संतान उत्पत्ति और उनके वैधीकरण को मान्यता देता है। साथ ही, जब वैवाहिक जीवन सुचारू नहीं होता, तो यह तलाक या विवाह विच्छेद के लिए आवश्यक तंत्र प्रदान करता है, जिससे दैनिक जीवन के मामलों का समाधान होता है ।

OR / अथवा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

हिन्दू कानून के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - हिन्दू कानून के स्रोतों का अध्ययन इसके विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। इसे दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

A. प्राचीन स्रोत:

1. **वेद या श्रुति** : इन्हें हिंदू धर्म के प्राथमिक ग्रंथ और ईश्वरीय कानून माना जाता है, जो स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए थे ।
2. **स्मृतियाँ :** ये वेदों में निहित नियमों की पूरक व्याख्या प्रदान करती हैं, हालांकि ये हमेशा स्पष्ट नहीं थीं और सभी स्थितियों को कवर नहीं करती थीं ।
3. **भाष्य और निबंध** : कानूनों के विश्लेषण, व्यवस्थापन और एकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनका विकास हुआ।
4. **रिवाज** : यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्रोत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

B. आधुनिक स्रोत :

1. **साम्या, न्याय और अच्छा अंतःकरण :** किसी विशिष्ट कानून के अभाव में या संघर्ष की स्थिति में, निष्पक्षता और न्याय के इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इसका मूल ब्रिटिश प्रशासन में है ।
2. **न्यायिक निर्णय :** न्यायालयों के फैसले हिंदू कानून का सबसे उपजाऊ और व्यावहारिक स्रोत माने जाते हैं।
3. **विधायिका** : यह एक अतिरिक्त स्रोत है जिसमें संसद द्वारा पारित अधिनियम शामिल हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)। ये अधिनियम हिंदू कानून के प्राचीन नियमों को घोषित, रद्द या संशोधित करते हैं ।

प्रश्न 43 - आपराधिक कानून में किन्हीं चार बचावों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – आपराधिक कानून में बचाव मुख्य रूप से 'दोषी मस्तिष्क' की अनुपस्थिति पर आधारित होते हैं। आपराधिक कानून में किन्हीं चार बचावों की व्याख्या :-

1. **दोषी इरादे का अभाव :** आपराधिक कानून का एक मूलभूत नियम है कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि उसे 'दोषी इरादे' के साथ न किया गया हो। इस सिद्धांत को लैटिन कहावत ***"actus non facit reum, nisi mens sit rea"*** द्वारा समझाया गया है । यदि किसी कार्य में दोषी मन शामिल नहीं है, तो वह अपराध नहीं बनता ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **अस्वस्थ मस्तिष्क :** यदि कोई व्यक्ति 'अस्वस्थ मस्तिष्क' का है, तो कानून यह मानता है कि उसने वह गलत कार्य बिना किसी दोषी इरादे के किया है। चूँकि उसे अपने कार्य की प्रकृति या उसके गलत होने का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता।
3. **नशा :** जिस प्रकार अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को छूट मिलती है, उसी प्रकार एक 'नशे में धुत व्यक्ति' को भी बचाव प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि नशे की हालत में व्यक्ति ने वह कार्य बिना किसी दोषी इरादे के किया है, अतः उसे दंडित नहीं किया जा सकता।
4. **अनजाने में किया गया कार्य :** यदि कोई व्यक्ति किसी को मारता है, तो वह केवल तभी उत्तरदायी होगा यदि वह प्रहार जानबूझकर किया गया हो । इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य अनजाने में या दुर्घटनावश होता है जहाँ इरादा मौजूद नहीं है, तो वह बचाव का आधार बन सकता है।

OR / अथवा

आपराधिक कानून के दो सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - आपराधिक कानून के दो सिद्धान्तों की व्याख्या :

1. **'मेन्स रिया' या दोषी मस्तिष्क का सिद्धांत :** यह आपराधिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उस कार्य के पीछे 'दोषी मन' न हो। अपराध गठित करने के लिए मानसिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल अपहरण करने के बारे में सोचता है लेकिन कोई कार्य नहीं करता, तो वह अपराधी नहीं है; इरादे के साथ कार्य का होना आवश्यक है।

2. **संयुक्त दायित्व का सिद्धांत :** सामान्यतः एक व्यक्ति केवल अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार होता है । लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में एक व्यक्ति को दूसरों के कार्यों के लिए भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से 38 और 149 आदि इससे संबंधित हैं।
   उदाहरण के लिए, यदि 'सामान्य उद्देश्य' वाली एक गैरकानूनी सभा का कोई सदस्य कोई अपराध करता है, तो उस सभा का प्रत्येक सदस्य उस कार्य के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 44 - ऐसे किन्हीं चार क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए जिनसे प्रक्रियात्मक कानून का संबंध है।

उत्तर - प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

1. **अधिकार क्षेत्र :** प्रक्रियात्मक कानून न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें संघर्ष के संदर्भ में और घरेलू संदर्भ में दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार शामिल हैं। यह निर्धारित करता है कि किस न्यायालय के पास किस मामले की सुनवाई का अधिकार है।
2. **कानूनी कार्यवाही और सुनवाई :** यह कानून पूरी कानूनी कार्यवाही को नियंत्रित करता है। इसमें समन , अभिवचन, और मुकदमे की सुनवाई शामिल है। यह वह तंत्र है जो मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से संबंधित है ।
3. **साक्ष्य और जांच तंत्र :** प्रक्रियात्मक कानून पुलिस और न्यायाधीशों द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने के तंत्र प्रदान करता है। इसमें तलाशी, गिरफ्तारी, जमानत और मुकदमे के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शामिल है।
4. **निर्णय और निष्पादन :** मुकदमे के अंत में निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया और उसके बाद उस निर्णय का निष्पादन भी इसी कानून के अंतर्गत आता है । यह अधिकारों को लागू करने या उनके उल्लंघन के लिए निवारण प्राप्त करने की विधि निर्धारित करता है।

प्रश्न 45 - सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को विश्लेषित कीजिए।

उत्तर - सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है वे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं, बिना किसी निचली अदालत में जाए। इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :-

1. **विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार :** अनुच्छेद 131 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय ढांचे से जुड़े विवादों को सुलझाने का एकमात्र अधिकार है। इसमें निम्नलिखित विवाद शामिल हैं:

a) भारत सरकार (संघ) और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

b) एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य, और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्य।

c) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद। भारत में किसी अन्य न्यायालय को ऐसे विवादों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है।

2. **रिट क्षेत्राधिकार :** सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके तहत न्यायालय को निम्नलिखित रिट जारी करने की शक्ति है:

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

a) **बंदी प्रत्यक्षीकरण :** किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत/नजरबंदी से मुक्त कराने के लिए।

b) **परमादेश :** किसी सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए।

c) **प्रतिषेध :** किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए।

d) **अधिकार पृच्छा :** किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधानिकता की जाँच करने के लिए।

e) **उत्प्रेषण :** किसी मामले को निचली अदालत या न्यायाधिकरण से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उसके निर्णय को रद्द करने के लिए।

इन रिटों के अलावा, न्यायालय कार्यपालिका को उचित निर्देश और आदेश भी जारी कर सकता है।

OR / अथवा

'न्यायिक सक्रियता' पद का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर - 'न्यायिक सक्रियता' भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक नई प्रवृत्ति है, जो मुख्य रूप से जनहित याचिका (PIL) के उदय के साथ सामने आई है। इसका विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है :-

1. **उत्पत्ति और अर्थ :** स्वतंत्रता के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने बदलते समाज की जरूरतों के अनुसार कानूनों को नया रूप देने का प्रयास किया है। जनहित याचिका (PIL), जिसे प्रो. उपेंद्र बख्शी ने "सामाजिक कार्रवाई याचिका" (Social action litigation) कहा है, ने न्यायिक सक्रियता के लिए नए रास्ते खोले हैं।
2. **उद्देश्य :** इसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी और गरीबों तक न्याय पहुँचाना है। यह उन लोगों को राहत प्रदान करता है जो पारंपरिक मुकदमेबाजी के कठोर और महंगे सिस्टम का सामना नहीं कर सकते।
3. **कार्यपालिका पर नियंत्रण :** न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका सरकारी मनमानी, लापरवाही और कार्यपालिका के उदासीन रवैये पर प्रभावी रोक लगाती है और उन्हें उनकी गलतियों के लिए जवाबदेह बनाती है।
4. **महत्वपूर्ण उदाहरण :** *केशवानंद भारती केस* (मौलिक अधिकार), *नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य* (हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा और 'संप्रभु प्रतिरक्षा' के दावे को खारिज करना) जैसे मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की रचनात्मक भूमिका और न्यायिक सक्रियता के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यह न्यायपालिका को सामाजिक न्याय का एक साधन बनाता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 46 - राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के संगठन का वर्णन कीजिए।

उत्तर - राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 4 के अनुसार, NGT एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है जिसमें कानूनी और पर्यावरण विशेषज्ञों का संतुलन होता है। इसकी संरचना निम्नलिखित है :

1. **अध्यक्ष :** अधिकरण का प्रमुख एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इस पद के लिए केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही योग्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से की जाती है।

2. **न्यायिक सदस्य :** अधिकरण में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होने चाहिए।ये सदस्य विधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और आमतौर पर उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो मामलों के कानूनी पहलुओं को देखते हैं।
3. **विशेषज्ञ सदस्य :** न्यायिक सदस्यों की तरह, विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या भी न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। इनके पास पर्यावरण विज्ञान, वन संरक्षण, या संबंधित विषयों में विशेष तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव (जैसे कि 15 वर्षों का प्रशासनिक या वैज्ञानिक अनुभव) होना अनिवार्य है।
4. **संरचना का उद्देश्य :** न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों का यह मिश्रण इसलिए बनाया गया है ताकि अधिकरण न केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करे, बल्कि जटिल वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मुद्दों (जैसे प्रदूषण का स्तर, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव) को भी सही ढंग से समझकर निर्णय ले सके।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 46 - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दो कार्य निम्नलिखित हैं :-

1. **उपभोक्ताओं का हित और कल्याण :** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एक मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिए कार्य करें। यह अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकता है ताकि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं मिल सकें। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रहे, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को फायदा हो।

2. **स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना :** आयोग का दूसरा प्रमुख कार्य देश की आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तेज और समावेशी विकास

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(inclusive growth) को बढ़ावा देना है। आयोग प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों (anti-competitive agreements) और बाजार में किसी संस्था द्वारा अपनी प्रमुख स्थिति (dominant position) के दुरुपयोग को रोकता है, ताकि सभी व्यवसायों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।

प्रश्न 47 - भारतीय संविधान में दिए गए 'स्वतंत्रता के अधिकार' के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर - संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 19-22) में निहित 'स्वतंत्रता का अधिकार' नागरिक स्वतंत्रता का मूल है। यह अधिकार व्यक्ति को कार्यपालिका के दमनकारी कृत्यों से बचाता है और लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अनिवार्य है। इसका महत्त्व निम्नलिखित बिंदुओं में विश्लेषण किया जा सकता है :-

1. **व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं (अनुच्छेद 19) :** यह नागरिकों को भाषण, सभा, संघ, भ्रमण, निवास और पेशे की छह स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये व्यक्तित्व विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।
2. **दोषसिद्धि से संरक्षण (अनुच्छेद 20) :** यह मनमाने दंड से बचाता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती और न ही उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
3. **जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा (अनुच्छेद 21) :** यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह गारंटी देता है कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी। इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें शिक्षा का अधिकार (21A) भी शामिल है।
4. **गिरफ्तारी से संरक्षण (अनुच्छेद 22) :** यह पुलिस की मनमानी को रोकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है।
5. **उचित प्रतिबंध :** ये अधिकार असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में राज्य इन पर 'उचित प्रतिबंध' लगा सकता है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाए रखता है।

OR / अथवा

आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े किन्हीं चार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को उजागर कीजिए।

उत्तर - संविधान के भाग-IV में वर्णित DPSP का मुख्य उद्देश्य भारत को एक 'कल्याणकारी राज्य' बनाना है। इससे जुड़े चार प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. **लोक कल्याण और सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 38) :** राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। यह आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **संसाधनों का उचित वितरण (अनुच्छेद 39) :** राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएगा कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलें और भौतिक संसाधनों का वितरण 'सामूहिक हित' में हो। यह धन के संकेंद्रण को रोकेगा और 'समान कार्य के लिए समान वेतन' सुनिश्चित करेगा ।

3. **काम की न्यायसंगत दशाएं (अनुच्छेद 42) :** राज्य काम के लिए मानवोचित और न्यायसंगत परिस्थितियां तैयार करेगा। इसमें महिलाओं के लिए 'प्रसूति सहायता' (Maternity Relief) का प्रावधान भी शामिल है ।

4. **निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग (अनुच्छेद 43) :** सभी कामगारों को एक शिष्ट जीवन स्तर और 'निर्वाह मजदूरी' सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 'कुटीर उद्योगों' को बढ़ावा देना भी राज्य का कर्तव्य है ।

प्रश्न 48 - वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की विभिन्न तकनीकों के महत्त्व को परखिए।

उत्तर - वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के अंतर्गत विवादों को सुलझाने की कई तकनीकें शामिल हैं, जिनका अपना-अपना महत्त्व है :-

1. **मध्यस्थता :** यह पारंपरिक मुकदमेबाजी की तुलना में कम खर्चीला और तेज है । इसमें एक या अधिक निष्पक्ष 'मध्यस्थ' (Arbitrators) होते हैं, जो विवाद सुनते हैं और एक निर्णय ('पंचाट' या Award) देते हैं जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है । यह वाणिज्यिक और तकनीकी विवादों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि मध्यस्थ उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है ।
2. **सुलह :** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तीसरा पक्ष ('सुलहकर्ता') विवाद को सुलझाने में मदद करता है । सुलहकर्ता विवाद के गुणों पर अपनी राय दे सकता है और एक समझौता निपटान का प्रस्ताव रख सकता है । यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक और गोपनीय होती है ।
3. **मध्यस्थता/मीडिएशन :** इसमें एक तटस्थ 'मध्यस्थ' (Mediator) पक्षों को बातचीत करने और समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है । वह सुलहकर्ता की तरह अपनी राय नहीं थोपता, बल्कि केवल संचार और समझौते को सुगम बनाता है । यह पारिवारिक और व्यक्तिगत विवादों के लिए बहुत प्रभावी है क्योंकि इसमें संबंधों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है।
4. **लोक अदालत :** यह भारत में ADR का एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित छोटे और सामान्य मामलों के भारी बोझ को कम करना है । यह कम खर्चीला है और त्वरित न्याय प्रदान करता है । लोक अदालत का निर्णय दीवानी अदालत की डिक्री के समान माना जाता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

5. **वार्ता :** यह सबसे आम तरीका है जहाँ पक्ष आपस में बात करके और सौदेबाजी करके समाधान निकालते हैं।

OR / अथवा

प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर - 'प्ली बार्गेनिंग' आपराधिक मामलों में विवाद समाधान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 265 A के तहत पेश किया गया है । इसका विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है :-

1. **अवधारणा :** प्ली बार्गेनिंग का अर्थ है कि यदि कोई आरोपी अपने ऊपर लगाए गए आरोप (offence alleged) को स्वीकार करने के लिए तैयार है (plead guilty), और पीड़ित के साथ मामले को सुलझाने (compromise) की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है ।
2. **शर्तें :** यह प्रक्रिया केवल न्यायालय की सहमति (consent of the Court) से ही संभव है। इसका उपयोग उन मामलों में नहीं किया जा सकता जो गंभीर अपराधों (heinous crimes) की श्रेणी में आते हैं।
3. **उद्देश्य** : इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य अदालतों के कार्यभार (work load) को कम करना और मामलों का त्वरित निपटान (speedy disposal) सुनिश्चित करना है ।
4. **लाभ** : इससे आरोपी को कम सजा मिल सकती है और पीड़ित को जल्दी न्याय मिल जाता है। यह अदालती प्रक्रिया के समय और खर्च को बचाता है। यह उन आपराधिक मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है जो मामूली प्रकृति (trivial in nature) के होते हैं।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 49 - खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया के किन्हीं चार प्रमुख बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया के चार प्रमुख बिंदु :-

1. **प्राधिकार प्राप्त करना :** यह प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है। कोई भी व्यक्ति या उद्योग जो खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, उसका संग्रह, परिवहन, भंडारण या निपटान करता है, उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से 'प्राधिकार' प्राप्त करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग के पास कचरे को संभालने की तकनीकी क्षमता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **पैकेजिंग और लेबलिंग :** खतरनाक कचरे को संभालने के दौरान सुरक्षा सर्वोपरि है। कचरे को ऐसे कंटेनरों में पैक किया जाना चाहिए जो रिसाव-रोधी हों। कंटेनरों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना आवश्यक है, जिस पर कचरे की प्रकृति, खतरे का प्रकार और आपातकालीन स्थिति के लिए निर्देश लिखे होने चाहिए ताकि परिवहन और भंडारण के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।
3. **सुरक्षित परिवहन :** खतरनाक अपशिष्ट का परिवहन केवल उन्हीं वाहनों से किया जाना चाहिए जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों। इसके अलावा, नियमों में कचरे की **'सीमा पार आवाजाही'** पर भी कड़े प्रावधान हैं ताकि एक राज्य या देश का कचरा अवैध रूप से दूसरे स्थान पर डंप न किया जा सके।
4. **उपचार और निपटान :** खतरनाक कचरे का निपटान खुले पर्यावरण में करना सख्त मना है। इसे केवल सरकार द्वारा अधिकृत 'सुरक्षित लैंडफिल साइटों' (Secure Landfills) या 'इंसिनरेटर' (भस्मीकरण संयंत्र) में ही नष्ट किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य मिट्टी और भूजल को जहरीला होने से बचाना है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 49 - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के किन्हीं चार तरीकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के चार प्रमुख तरीके:

1. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 :** इसे उपभोक्ताओं का 'मैग्ना कार्टा' माना जाता है। यह अधिनियम दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है । यह उपभोक्ताओं को आसानी से और कम खर्च में न्याय पाने का कानूनी ढांचा देता है ।
2. **त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र :** उपभोक्ताओं को त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने के लिए अधिनियम के तहत तीन स्तरों पर अर्ध-न्यायिक व्यवस्था की गई है: (a) जिला फोरम, (b) राज्य आयोग, और (c) राष्ट्रीय आयोग । असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता ऊपरी स्तर पर अपील भी कर सकता है ।
3. **उपभोक्ता जागरूकता :** उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उन्हें उनके 6 अधिकारों (सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और शिक्षा) के प्रति जागरूक करना आवश्यक है । सरकार "जागो ग्राहक जागो" अभियान के माध्यम से यह कार्य करती है ।
4. **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद :** यह परिषद उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए नीतियां बनाती है । यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता और कीमत पर वस्तुएं प्राप्त हों ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

NIOS PYQ's SOLUTIONS

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS & ANSWERS

OCTOBER-2025

Your Path to Success

खंड - अ

Q1 निम्नलिखित में से कौन सा एक मुस्लिम कानून का स्रोत नहीं है?

(A) कियास

(B) कुरान

(C) स्मृतियाँ

(D) हदीस

उत्तर – (C) स्मृतियाँ

Q2 वैध हिन्दू विवाह के लिए दुल्हन (वधु) की सही आयु चुनिये।

(A) 21 वर्ष

(B) 18 वर्ष

(C) 22 वर्ष

(D) 19 वर्ष

उत्तर - (B) 18 वर्ष

Q3 निम्नलिखित में से कौन सा एक दण्ड का सिद्धान्त नहीं है ?

(A) निवारक सिद्धान्त

(B) निरोधक सिद्धान्त

(C) सुधारात्मक सिद्धान्त

(D) धार्मिक सिद्धान्त

उत्तर - (D) धार्मिक सिद्धान्त

Q4 प्रत्येक अभिवचन का निम्नलिखित में से किस से सम्बन्ध होता है ?

(A) तथ्यों के उल्लेख से

(B) कानूनों के उल्लेख से

(C) दण्ड के उल्लेख से

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(D) निर्णयों के उल्लेख से

उत्तर - (A) तथ्यों के उल्लेख से

Q5 अपराध के बारे में असत्य कथन को चुनिये।

(A) कानूनों का उल्लंघन करने का कार्य

(B) समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह का कार्य

(C) कानून द्वारा प्रतिबंधित कार्य करना

(D) राजनीतिक प्रचार करने का कार्य

उत्तर - (D) राजनीतिक प्रचार करने का कार्य

Q6 भारतीय दण्ड संहिता के चतुर्थ अध्याय में दर्ज प्रतिरक्षा की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है?

(A) न्यायिक विधियां

(B) तथ्य की भूल

(C) धार्मिक गुरु का कृत्य

(D) अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य

उत्तर - (C) धार्मिक गुरु का कृत्य

Q7 अधिष्ठायी कानून के बारे में 'गलत' कथन को चुनिए।

(A) इन्हें मूलतः संविधान से लिया जाता है।

(B) यह व्यक्तियों के बीच संबंध से जुड़े होते हैं।

(C) यह सभी सार्वजनिक और निजी कानूनों से जुड़े होते हैं।

(D) यह उन नियमों को निर्धारित करते हैं जिनकी सहायता से कानून लागू किए जाते हैं।

उत्तर - (D) यह उन नियमों को निर्धारित करते हैं जिनकी सहायता से कानून लागू किए जाते हैं।

Q8 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रियात्मक कानून है ?

(A) अपील करने का अधिकार

(B) सम्पत्ति का कानून

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(C) तीव्र मुकदमे का अधिकार

(D) अनुबंध का कानून

उत्तर - (C) तीव्र मुकदमे का अधिकार

Q9 निम्नलिखित में से कौन सा कानून निजी कानून है ?

(A) संवैधानिक कानून

(B) प्रशासनिक कानून

(C) पारिवारिक कानून

(D) आपराधिक कानून

उत्तर - (C) पारिवारिक कानून

Q10 निम्नलिखित में से किसके साथ लोक कानून का सम्बन्ध नहीं है?

(A) सरकार का ढांचा

(B) विरासत (वसीयत) के नियम

(C) अधिकारियों की शक्तियां

(D) अधिकारियों के कर्तव्य

उत्तर - (B) विरासत (वसीयत) के नियम

Q11 प्राचीन काल में वैकल्पिक विवाद समाधान की कौन सी विधि लोकप्रिय थी ?

(A) विवाचन

(B) मध्यस्थता

(C) लोक अदालत

(D) समझौता

उत्तर - (B) मध्यस्थता

Q12 मध्यस्थता विवाद सुलझाने की एक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित में से किसकी सहायता ली जाती है ?

(A) मुकदमा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(B) एक स्वतंत्र तीसरा व्यक्ति

(C) पंचायत

(D) मानवाधिकार

उत्तर - (B) एक स्वतंत्र तीसरा व्यक्ति

Q13 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्ली बार्गेनिंग के बारे में गलत है ?

(A) मुकदमे से पहले अपराधी और अभियोजक के बीच बातचीत

(B) इससे अदालतों को मुकदमों के बोझ के प्रबन्धन में सहायता मिलती है।

(C) यह अदालतों के कार्यबोझ को बढ़ाती है।

(D) इससे तीव्र समाधान ढूंढने में सहायता मिलती है।

उत्तर - (C) यह अदालतों के कार्यबोझ को बढ़ाती है।

Q14 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्ली-बार्गेनिंग का प्रकार नहीं है ?

(A) दोष बार्गेनिंग

(B) दण्ड (सज़ा) बार्गेनिंग

(C) तथ्य बार्गेनिंग

(D) फीस बार्गेनिंग

उत्तर - (D) फीस बार्गेनिंग

Q15 निम्नलिखित में से कौन संविधान समिति का अध्यक्ष था ?

(A) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

(B) जवाहरलाल नेहरू

(C) महात्मा गांधी

(D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

उत्तर - (D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Q16 निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है ?

(A) प्रभुसत्ताक

(B) समाजवादी

(C) संसद

(D) लोकतान्त्रिक

उत्तर - (C) संसद

Q17 राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है?

(A) 25 वर्ष

(B) 27 वर्ष

(C) 30 वर्ष

(D) 35 वर्ष

उत्तर - (C) 30 वर्ष

Q18 लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ?

(A) 4 वर्ष

(B) 5 वर्ष

(C) 6 वर्ष

(D) 7 वर्ष

उत्तर - (B) 5 वर्ष

Q19 निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है ?

(A) महाराष्ट्र

(B) मध्य प्रदेश

(C) उत्तर प्रदेश

(D) पश्चिम बंगाल

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

उत्तर - (C) उत्तर प्रदेश

Q20 सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है?

(A) अनुच्छेद 32

(B) अनुच्छेद 34

(C) अनुच्छेद 35

(D) अनुच्छेद 36

उत्तर - (A) अनुच्छेद 32

Q21 निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए:

A	B
(i) हिन्दू धर्म	(a) कुरान
(ii) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925	(b) यहूदी (ईसाई)
(iii) इस्लाम	(c) स्मृतियाँ
(iv) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869	(d) पारसी और ईसाई

उत्तर -

(i) - (c)

(ii) - (d)

(iii) - (a)

(iv) - (b) (ईसाई)

वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिये (प्र. सं. 22 से 26)

Q22 भारतीय ईसाई विवाह _______ को वर्ष _______ में कानून का रूप दिया गया।

उत्तर - अधिनियम, 1872

Q23 आपराधिक कानून में _______ को अनेक प्रकार के _______ उपलब्ध हैं।

उत्तर - दोषी, बचाव

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Q24 किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने से ______ न्यायालय को अपनी अधिकार सीमा के उल्लंघन से बचने के लिए ______ रिट जारी की जाती है।

उत्तर - अधीनस्थ, प्रतिषेध

Q25 भारत में संविधान भारत को प्रभुसत्ताक, ______ , धर्म निरपेक्ष, ______ गणराज्य बनाता हैं।

उत्तर - समाजवादी, लोकतान्त्रिक

Q26 एक बच्चा जिसकी आयु ______ वर्ष से कम है वह ______ मंशा के लिए अक्षम है। यह साक्ष्य का नियम है।

उत्तर - आठ, आपराधिक

Q27 प्रत्येक वाक्य के सामने सत्य अथवा असत्य लिखें

(i) न्यायाधीश कानून को रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्तर - सत्य

(ii) सामान्य रूप में, सभी कानून पूर्वव्यापी होते हैं बशर्ते विधान ऐसा विनिर्दिष्ट करे

उत्तर - सत्य

Q28 प्रत्येक वाक्य के सामने सत्य अथवा असत्य लिखें।

(i) सिविल प्रक्रियात्मक कानून में ऐसे नियम और मानक शामिल होते हैं जिनका अदालतें सिविल मुकदमों में पालन करती हैं।

उत्तर - सत्य

(ii) संविधान कानून निजी कानून की एक शाखा है।

उत्तर - असत्य

कारण: संवैधानिक कानून 'लोक कानून' या 'जन-कानून' की एक शाखा है।

Q29 रिक्त स्थान भरिये।

लोक अदालतें ______ के ______ वर्ग के हित में होती हैं

उत्तर - समाज, कमजोर

Q30 रिक्त स्थान भरिये :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

भारत का संविधान एक ______ से शुरू होता है जिसमें संविधान के आदर्श, ______ और आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है।

उत्तर - प्रस्तावना, उद्देश्यों

Q31 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(i) भारत के संविधान द्वारा कितनी स्वतंत्रताओं की गारन्टी प्रदान की गई हैं?

उत्तर - छः स्वतंत्रताओं

(ii) किस अवधि में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है ?

उत्तर - आपातकाल की स्थिति में।

Q32 सत्य या असत्य अंकित करें :

(i) धन विधेयक को केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

उत्तर – असत्य

कारण: धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग केवल लोकसभा के सदस्य ही कर सकते हैं।

उत्तर – सत्य

Q33 सत्य या असत्य अंकित करें :

(i) संसद को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बदलने का अधिकार है।

उत्तर – असत्य

कारण: संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है परन्तु उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।

(ii) भारत में पाँच राज्यों में द्विसदनीय विधायिका हैं।

उत्तर – सत्य

Q34 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(i) संघ में सरकार का मुखिया कौन होता है ?

उत्तर – प्रधानमंत्री

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(ii) संसद के किस सदन को निम्न सदन कहते हैं ?

उत्तर – लोक सभा

Q35 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) भारत का सर्वोच्च न्यायलय किस नगर में अवस्थित है ?

उत्तर – दिल्ली

(ii) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक पद पर बने रह सकता है?

उत्तर – 62 वर्ष

खंड – ब

Q36 हिन्दू कानून में उत्तराधिकार के कोई दो प्रकार स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – हिन्दू कानून में उत्तराधिकार के दो प्रकार हैं -

1. **वसीयती उत्तराधिकार:** इसमें व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण अपनी वसीयत के अनुसार करता है।
2. **निर्वसीयत उत्तराधिकार:** इसमें बिना वसीयत किए मृत्यु होने पर कानून के अनुसार व्यक्ति की संपत्ति को उसके वैध उत्तराधिकारियों में बाँट दिया जाता है।

Q37 'प्रारूपण' के किन्हीं दो सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – 'प्रारूपण' के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत 'आयोजन' और 'लेखन' हैं।

1. **आयोजन:** इसमें कानूनी दस्तावेज़ के उद्देश्य और उसकी संरचना को व्यवस्थित रूप से निर्धारित किया जाता है।
2. **लेखन:** इसमें दस्तावेज़ को स्पष्ट, संक्षिप्त, सटीक तथा सरल भाषा में लिखा जाता है।

अथवा

'एक्टस रीयस' पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – 'एक्टस रीयस' का अर्थ 'दोषपूर्ण कार्य' है। यह अपराध का भौतिक तत्व है, अर्थात ऐसा स्वैच्छिक कार्य या चूक जो कानून द्वारा निषिद्ध हो। किसी अपराध के लिए सामान्यतः एक्टस रीयस का होना आवश्यक माना जाता है।

Q38 'सूचना का अधिकार' के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आती है और अनावश्यक देरी कम होती है। इसके द्वारा नागरिक सरकारी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और सरकार की जवाबदेही बढ़ाने में सहायता मिलती है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Q39 संविधान की प्रस्तावना की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और मौलिक नियमों को स्पष्ट करती है। यह संविधान की मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है तथा संविधान के विभिन्न प्रावधानों और अन्य कानूनों की व्याख्या करने में सहायता करती है।

अथवा

भारत के संविधान में शामिल 'मौलिक कर्तव्यों' के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – मौलिक कर्तव्य नागरिकों को संविधान का पालन करने, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करने और भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। नागरिक इनके पालन से अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनते हैं।

Q40 'नीति निदेशक सिद्धान्तों' के दार्शनिक आधार को उजागर कीजिए।

उत्तर – नीति निदेशक सिद्धान्तों का दार्शनिक आधार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। इनमें फ्रांस के मानवाधिकारों, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा, उदारवादी सामाजिक दर्शन, फैबियन समाजवाद तथा गांधीवादी सर्वोदय के विचारों को भी लिया गया है।

वैकल्पिक मॉड्यूल - 7A

Q41 पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – 'पर्यावरण' का अर्थ जल, वायु, भूमि, मनुष्य, अन्य जीव-जन्तु और इनके बीच का पारस्परिक संबंध है। सरल शब्दों में, हमारे आसपास की सभी प्राकृतिक और जैविक वस्तुएँ पर्यावरण हैं।

वैकल्पिक मॉड्यूल - 7B

Q41 'एकाधिकार' पद के अर्थ की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – एकाधिकार का अर्थ है कि बाज़ार में किसी वस्तु की पूर्ति करने वाला केवल एक ही व्यक्ति या संस्था हो। कानून की दृष्टि में, एकाधिकार ऐसी व्यापारिक इकाई है, जिसके पास बाज़ार पर इतना नियंत्रण होता है कि वह बाज़ार की कीमतें तय करने में सक्षम होती है।

Q42 मिश्रित कानून प्रणाली की कोई दो विशेषताएं स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – मिश्रित कानून प्रणाली की दो मुख्य विशेषताएँ-

1. **विभिन्न कानूनों का समन्वय:** इसमें अलग-अलग कानूनी परंपराओं और प्रणालियों के नियमों का समन्वय होता है, जिससे यह अधिक व्यापक और प्रभावी बनती है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **न्यायिक निर्णय और कानून का मेल:** यह प्रणाली न्यायालयों के निर्णयों तथा वैधानिक कानूनों, दोनों के आधार पर विकसित होती है। इसलिए इसमें समय के अनुसार बदलाव करने का लचीलापन होता है।

अथवा

पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम के अन्तर्गत तलाक के लिए कोई चार आधार स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम के अन्तर्गत तलाक के लिए निम्नलिखित चार आधार हैं-

1. **विवाह की गैर-सम्पूर्णता:** विवाह के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित न होना।
2. **क्रूरता:** पति या पत्नी द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता करना।
3. **सात वर्ष की कैद:** यदि किसी पक्ष को सात वर्ष के कारावास का दण्ड मिला हो।
4. **परित्याग:** यदि पति या पत्नी एक-दूसरे से अलग रहे और कोई वैवाहिक अंतरसंबंध न रखे।

Q43 विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत कानून सेवाएं प्राप्त कर सकने वाले चार प्रकार के व्यक्तियों को उजागर कीजिए।

उत्तर – विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है-

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
2. मानव तस्करी या बेगार का शिकार व्यक्ति।
3. महिला या बच्चा।
4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति।

अथवा

वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के कोई चार लाभ उजागर कीजिए।

उत्तर – वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) पद्धति के चार प्रमुख लाभ-

1. यह अदालत की तुलना में कम समय में विवाद का समाधान करती है।
2. इसमें खर्च कम आता है, इसलिए यह किफायती होती है।
3. इसकी प्रक्रिया सरल और कम औपचारिक होती है।
4. विवाद आपसी सहमति से सुलझते हैं, जिससे दोनों पक्षों के आपसी संबंध बने रहते हैं।

इस प्रकार, ADR समय, धन और श्रम की बचत करते हुए विवादों का प्रभावी समाधान प्रदान करती है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Q44 मौलिक अधिकारों की कोई चार विशेषताएं स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – मौलिक अधिकारों की चार प्रमुख विशेषताएँ-

1. ये भारतीय संविधान के भाग-III में दिए गए हैं।
2. ये न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है।
3. ये पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं, बल्कि ज़रूरत के समय इन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
4. इनका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना तथा राज्य की मनमानी पर नियंत्रण रखना है।

अथवा

मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच कोई चार अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर – मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच चार अंतर-

मौलिक अधिकार	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
1. ये न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं।	1. इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।
2. ये नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं।	2. ये राज्य को दिशा-निर्देश देते हैं।
3. इनका उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है।	3. इनका उद्देश्य समाज के कल्याण को बढ़ावा देना है।
4. ये राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।	4. ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

वैकल्पिक मॉड्यूल - 7A

Q45 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) पर्यावरण से जुड़े विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए बनाया गया एक विशेष न्यायाधिकरण है। इसे पर्यावरण, वन और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों की विशेष जानकारी होती है। इसलिए यह ऐसे मामलों का जल्दी और प्रभावी ढंग से निपटारा करता है। इससे सामान्य अदालतों का बोझ भी कम होता है तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Q46 धारणीय विकास में क्या-क्या शामिल होता है? किन्हीं चार की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – धारणीय विकास में निम्नलिखित तत्त्व शामिल होते हैं-

1. बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, ताकि उनका संरक्षण बना रहे।
3. पर्यावरण संरक्षण करना, जिससे प्रदूषण और पर्यावरण का क्षरण कम हो।
4. आर्थिक विकास और पर्यावरण में संतुलन होना, ताकि विकास के साथ प्रकृति और समाज का भी कल्याण हो।

वैकल्पिक मॉड्यूल - 7B

Q45 भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के किन्हीं चार कार्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के चार प्रमुख कार्य-

1. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
2. देश में आर्थिक गतिविधियों में स्वस्थ और उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।
3. आर्थिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों को लागू करना।
4. प्रतिस्पर्धा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाए रखना, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

Q46 भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण की प्रणाली का आकलन कीजिए।

उत्तर – भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली त्रि-स्तरीय है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को सरल, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराती है। इसमें बिना वकील के भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिससे आम व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह प्रणाली दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रभावी रक्षा करती है।

Q47 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विचार किए व लागू किए किन्हीं चार उपायों एवं योजनाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा विचार किए व लागू किए गए चार प्रमुख उपाय एवं योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

1. इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए नीतियों एवं सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया, जिससे गरीब एवं कमजोर वर्गों को न्याय सुनिश्चित हुआ।
2. सस्ती एवं प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएँ बनाई गईं, जिससे समाज के वंचित वर्गों को न्याय प्राप्त करना सरल हुआ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

3. ग्रामीण क्षेत्रों, झुग्गी-झोपड़ियों तथा कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कानूनी सहायता शिविर लगाए गए, जिससे लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का समाधान प्रोत्साहित हुआ।
4. मध्यस्थता, सुलह एवं पंचाट के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा दिया गया, जिससे त्वरित एवं कम खर्चीला न्याय संभव हुआ।

अथवा

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) की किन्हीं चार तकनीकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की चार प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं-

1. **विवाचन:** इसमें विवादित पक्ष आपसी सहमति से एक या अधिक विवाचकों को नियुक्त करते हैं, जो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हैं। यह निर्णय बाध्यकारी होता है और न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है।
2. **समझौता:** इसमें एक तटस्थ मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनाने में सहायता करता है, परन्तु वह कोई निर्णय नहीं देता। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक और लचीली होती है।
3. **मध्यस्थता:** इसमें एक निष्पक्ष तीसरा व्यक्ति विवादित पक्षों को बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है, लेकिन निर्णय नहीं देता।
4. **लोक अदालत:** इसमें विवादों का निपटारा आपसी सहमति से त्वरित एवं कम खर्च में किया जाता है तथा इसका निर्णय न्यायालय के समान प्रभावी होता है।

Q48 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर्गत जारी की जा सकने वाली किन्हीं तीन याचिकाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – तीन याचिकाओं का महत्व-

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण:** यह याचिका अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इसके माध्यम से न्यायालय संबंधित व्यक्ति को तुरंत प्रस्तुत करने का आदेश देता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित होती है।
2. **परमादेश:** इसके द्वारा उच्च न्यायालय सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके विधिक कर्तव्यों के पालन का आदेश देता है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है और जनता के अधिकारों की रक्षा होती है।
3. **निषेधादेश:** यह याचिका निम्न न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनुशासन और अधिकार सीमा का पालन सुनिश्चित होता है तथा न्यायिक अतिक्रमण रोका जाता है।

अथवा

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में से लागू किए जा चुके किन्हीं तीन सिद्धान्तों की जाँच कीजिए।

उत्तर – राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में से लागू किए जा चुके तीन सिद्धान्त हैं-

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. **अनुच्छेद 39 (संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण):** इसके अंतर्गत भूमि सुधार लागू किए गए, जिनसे जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, भूमि सीमा निर्धारित की गई और अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरित की गई। इससे आर्थिक समानता बढ़ी।
2. **अनुच्छेद 40 (पंचायती राज):** इसके क्रियान्वयन के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिससे ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी और स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया।
3. **अनुच्छेद 45 (शिक्षा का अधिकार):** 86वें संविधान संशोधन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इससे शिक्षा का विस्तार हुआ।

वैकल्पिक मॉड्यूल - 7A

Q49 खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रियाएँ-

1. **उत्पत्ति की पहचान:** सर्वप्रथम उन उद्योगों की पहचान की जाती है जहाँ खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिससे उनके स्रोत का निर्धारण हो सके।
2. **आँकड़ों का संकलन:** पहचाने गए उद्योगों से संबंधित अपशिष्ट उत्पादन का सर्वेक्षण कर विस्तृत आँकड़े एकत्र किए जाते हैं, जिससे उनकी मात्रा और प्रकृति समझी जा सके।
3. **विशिष्टीकरण:** अपशिष्ट पदार्थों की भौतिक, रासायनिक एवं विषाक्त विशेषताओं का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, जिससे उनकी खतरनाक प्रकृति स्पष्ट होती है।
4. **निपटान स्थल की पहचान:** अपशिष्ट के उपचार, भंडारण एवं निपटान हेतु उपयुक्त स्थल चुना जाता है तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाता है।
5. **ट्रीटमेंट व कार्यान्वयन:** निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट का सुरक्षित उपचार, भंडारण और निपटान किया जाता है तथा इसकी नियमित निगरानी की जाती है।

वैकल्पिक मॉड्यूल 7B

Q49 भारत में उपभोक्ता आन्दोलन के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित में संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में अनैतिक व्यापार, जमाखोरी और मिलावट के विरोध में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को संगठित कर उनके अधिकारों की रक्षा करना था। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के हित में संसद द्वारा कई विभिन्न अधिनियम पारित हुए -

1. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:** उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न स्तरों स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम/आयोगों की स्थापना की गई।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **उपभोक्ता संरक्षण परिषदें:** उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर परिषदों का गठन किया गया।
3. **विवाद निवारण तंत्र:** उपभोक्ता शिकायतों के जल्द एवं सरल समाधान के लिए जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Thank you!

We hope you found this material helpful. We wish you the very best for your examination.

Strive for Excellence – Your Path to Success